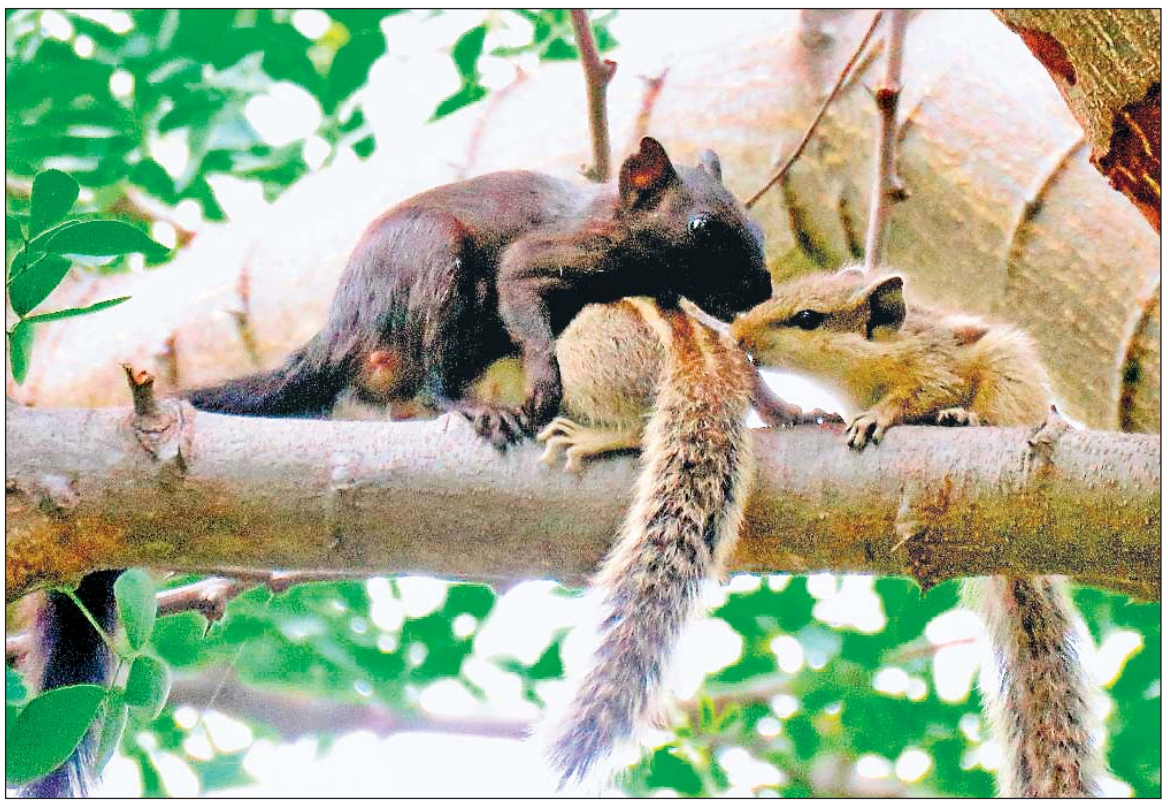

उदयपुर के सागवाड़ा क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ एवं अनोखी काली गिलहरी दिखाई दी है। नेचर एक्टिविस्ट मुकेश पंवार ने इस गिलहरी की तस्वीरें ली हैं। उन्होंने बताया कि, राजस्थान में इस तरह की गिलहरी मिलने की यह पहली घटना है।

उदयपुर संभाग के सागवाड़ा में दिखी काली गिलहरी

वागड़ नेचर क्लब के तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार ने गिलहरी की तस्वीरें ली हैं

- **यह असल में सामान्य गिलहरी है, जो दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति ''मैलनिज़्म'' से ग्रस्त है, जिसमें त्वचा व फर में ब्लैक पिगमैंट की मात्रा बढ़ जाती है, इसी कारण यह गिलहरी काले रंग की है।**
- **इससे पहले उदयपुर संभाग में ''ल्युसिस्किट कॉमन किंगफिशर'' देखा गया था। यह भी एक आनुवंशिक स्थिति है इसमें त्वचा व फर में पिगमैंट नहीं होता है।**

उदयपुर, 29 अगस्त (कासं)। उदयपुर संभाग के सागवाडा शहर के समीप दुर्लभ काली गिलहरी दिखाई दी है। राजस्थान में अपनी तरह की ऐसी पहली काली गिलहरी को खोजने, क्लिक करने और पुष्टि करने का श्रेय वागड नेचर क्लब के सदस्य ख्यातनाम तितली विशेषज्ञ मुकेश पंवार को जाता है।

पंवार ने बताया कि मैलानिस्टिक गिलहरी अक्सर मिलती है लेकिन एकदम गहरी काली गिलहरी मिलना बेहद दुर्लभ होता है। उन्होंने कहा इस गिलहरी के रोएं, आंखे, पूंछ सब काला है। ज्ञातव्य है कि शहर के दो अलग-अलग स्थानों पर काली गिलहरी देखी है। पहले तो लगा कि यह गिलहरी जैसा कोई अन्य जीव है पर चार दिन तक उसके व्यवहार को देखा तो यकीन हो गया कि यह गिलहरी है। इस मादा गिलहरी के दो बच्चे भी हैं जो सामान्य हैं।

सर्प विशेषज्ञ धर्मेन्द्र व्यास ने बताया कि सामान्यतया समस्त जीवों की त्वचा का रंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित रहता है परन्तु लाखों में एक जीव मैलानिस्टिक (गहरे या काले रंग) में हो सकता है। इसमें त्वचा में या फर में ब्लैक पिगमैंट "मैलनिन" की मात्रा बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के जंगल में ब्लैक टाईगर तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में ब्लैक पैंथर दिख चुके हैं। ठीक उसी तरह ये काली गिलहरियां भी सागवाडा क्षेत्र में दिखी हैं। इस दुर्लभ जीव की साईटिंग पर वागड नेचर क्लब के डॉ. कमलेश शर्मा, वीरेन्द्रसिंह बेडसा, रुपेश भावसार, विनय दवे सहित अन्य सदस्यों सहित संभागभर के प्रकृति व पर्यावरण विशेषज्ञों ने खुशी जताई है।

प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में काली गिलहरी की साईटिंग का कोई आधिकारिक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, संभवत: राजस्थान का यह पहला मामला है। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता के कारण वागड-मेवाड अंचल दुर्लभ प्रजातियों के जीवों के लिए बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। हाल ही में यहां ल्युसिस्टिक किंग फिशर भी दिखा था। इस तरह का किंग फिशर विश्व में तीन बार ही दिखा है। उनमें से एक उदयपुर है। यह भी एक तरह की आनुवंशिक स्थिति है इसमें त्वचा, फर आदि में मैलनिन पिगमैंट का अभाव होता है।

प्रदेश में कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठन हुए बेघर, सामान रखने की भी जगह नहीं

जिन भवनों में इनके मुख्यालय थे, उन्हें खाली करवा लिया गया है

- **अस्पताल रोड स्थित जिस बंगले को प्रदेश मुख्यालय बनाया जाना था, वह अब बनेगा वॉर रूम।**
- **राजस्थान में, 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से पार्टी का नया प्रदेश मुख्यालय बनाए जाने की बात हो रही है, पर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।**

जयपुर, 29 अगस्त (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस की अपनी सरकार होते हुए भी पार्टी अपने लिए नया भवन नहीं बना पाई है। यह बात चर्चाओं में हमेशा रहती है, लेकिन अब इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पास जो प्रदेश कार्यालय था,वह भी खाली करा लिया गया है। अब कांग्रेस के तीन प्रमुख अग्रिम संगठन, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवादल बिना कार्यालय के हो गए हैं। हालात यह है कि अब इन तीनों कार्यालयों के अध्यक्षों के पास बैठने की जगह नहीं है और बैठने की बात तो दूर इनके पास अपना फर्नीचर रखने का स्थान भी नहीं है।

दरअसल राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से कांग्रेस का नया प्रदेश मुख्यालय ढूंढा जा रहा था। उसी दौरान अस्पताल मार्ग पर एक बंगला कांग्रेस ने अपने अधीन किया और कहा गया कि इसे प्रदेश मुख्यालय बनाया जाएगा। बाद में कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल का लगातार विस्तार हो रहा है और यदि यहां कांग्रेस मुख्यालय बनाया गया तो भीड़भाड़ के चक्कर में यहां कई एंबुलेंस फंसेगी और यदि कोई अनहोनी हो गई तो वह कांग्रेस के सिर आएगी। ऐसे में यहां कांग्रेस मुख्यालय बनाने के विचार को स्थगित कर दिया गया। लेकिन तय किया गया कि अस्पताल रोड वाले बंगले में वॉर रूम बनाया जाएगा।

यह बंगला कांग्रेस ने अपने नाम आवंटित करवा लिया था। सवाई जयसिंह हाईवे स्थित सरकारी बंगला जिसमें कि पिछले 30 से ज्यादा सालों से कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस सेवादल के प्रदेश मुख्यालय चल रहे थे, उसे खाली किया जाना भी जरूरी था। ऐसे में सोमवार को तीनों अग्रिम संगठनों को कार्यालय खाली करने के लिए कह दिया गया। अब समस्या यह रही कि तीनों कार्यालयों का फर्नीचर और अन्य सामग्री आखिरकार कहां रखी जाए। तीनों संगठनों के अध्यक्षों ने इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस से चर्चा की तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उन्हें बैठने के लिए स्थान देने में चार-पांच दिन का समय लग जाएगा। वे सामान रखने की व्यवस्था अपने स्तर पर कर ले, लेकिन यह व्यवस्था सोमवार दोपहर बाद तक नहीं हो पाई। अत: ऐसे में थोड़ा बहुत सामान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रखवाया गया। वहीं कागजात तीनों अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते रहे।

मजेदार बात यह है कि वर्ष 1998 के बाद से अशोक गहलोत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो प्रदेश कांग्रेस खुद के लिए नया मुख्यालय और ना ही अपने अग्रिम संगठनों के लिए कोई स्थान चिन्हित कर पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के लिए मानसरोवर में स्थान चिन्हित किया गया है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब बीच शहर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मानसरोवर में कितने लोग पहुंचेंगे, क्योंकि वह स्थान शहरी क्षेत्र से बहुत दूर है।

इसके बाद तय किया गया कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ही तीनों अग्रिम संगठनों को कमरे आवंटित किए जाएंगे,लेकिन यहां भी समस्या यह है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कमरों की संख्या सीमित है। ऐसे में यदि इन तीनों अग्रिम संगठनों को कमरे आवंटित भी कर दिए जाते हैं, तो बैठने की जगह नहीं बचेगी। खुद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी ना तो प्रदेश कांग्रेस के पास अपना खुद का बड़ा मुख्यालय बनाने की जमीन तय की गई और अब जब अग्रिम संगठनों से मुख्यालय खाली करवा लिया गया है, तो उनके लिए भी स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है।

तमिलनाडू में मंदिरों के मैनेजमैंट पर काबिज...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया गया था। उस समय, चिदम्बरम जिले के इस प्राचीन एवं प्रख्यात मंन्दिर के पुजारी समुदाय (ब्राहमण) के बचाव के लिये, अन्नामलाई तुरन्त आगे आ गये थे। सुब्रमन्यम स्वामी, जो तमिलनाडु के निवासी है तथा स्वयं को हिन्दू-अधिकारों के प्रबल हिमायती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ने अपनी इस ताजा मुहिम के जरिये, मन्दिरों को सरकार के नियन्त्रण से बाहर रखने की लड़ाई को अब अपने हाथों में ले लिया है। जहाँ तक दूसरे मुद्दे-गैर ब्राहमण पुजारियों की नियुक्ति का प्रश्न है, इसे मद्रास उच्च न्यायालय करीब-करीब तय कर ही चुका है। न्यायालय ने पुजारियों की नियुक्ति के लिये कुछ प्रतिबन्ध एवं शर्ते तय कर दी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने, जहाँ गैर-ब्राहमणों को पुजारी नियुक्त किये जाने के सरकारी निर्णय पर रोक लगा दी है, वहीं अदालत ने सरकार को उन मन्दिरों में पुजारी नियुक्त किये जाने पर भी रोक लगा दी है, जिन मन्दिरों का निर्माण "आमा शास्त्रों" के अनुसार हुआ है। उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि सरकार राज्य के अन्य सभी मन्दिरों में किसी भी जाति के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त कर सकती हैं। लेकिन राजनैतिक विश्लेषक सुमन्त सी.रमन. का मानना है कि मन्दिर और धर्म से सम्बन्धित इस प्रकार के मुद्दों, जो ब्राहमण समुदाय के पक्ष में दिखाई देते हैं, को उठाने से भाजपा को कोई मदद मिलने की कोई खास सम्भावना नहीं है।

इन्ही विचारों को दोहराते हुये, मद्रास विश्वविद्यालय के प्रौ. रामू मणिवन्नन का कहना है कि वस्तुत: इस प्रकार के मुद्दों को उठाकर, भाजपा डी.एम.के. को राजनैतिक लाभ पहुँचा रही हैं। अब, सर्वोच्च न्यायालय पहुँचकर, भाजपा तथा उसके समर्थकों ने, एक समुदाय विशेष का पक्ष लेकर, इस बहस को जीवित रखा है तथा इससे तमिलनाडु में पार्टी को कोई मदद नहीं मिलने वाली है क्योंकि वहाँ ब्राहमण बहुत कम संख्या में हैं।

प्रौ. मणिवन्नन ने आगे कहा, "इसने (भाजपा) ने इस बहस को जीवित रखा है तथा इस प्रकार इसने डी.एम.के. को एक अवसर दे दिया है कि वह सभी समुदायों के लोगों को पुजारी बनाने के अपने प्रयासों को और तेज कर सके क्योंकि ऐसा किया जाना उसकी विचारधारा से तो मेल खाता ही है, उसके वोट बैंक को भी माफिक आता हैं।"

'गुलाम नबी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें अंधाधुंध तरीके से इन्टरव्यू देकर पार्टी को बदनाम करने का काम दिया गया है, जिससे वो अपने आप को और नीचे गिरा रहे हैं।"

क्या गुलाम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी के पास एक ही तरीका है कि नैशनल कॉन्फ्रैंस को घाटी में एकतरफा जीत दर्ज करने से रोका जाए। जहां तक जम्मू क्षेत्र का सवाल है, परिसीमन के बाद भाजपा की स्थिति और सुरक्षित हो गई है क्योंकि नए विधानसभा क्षेत्रों के वोटर भाजपा के पक्ष के प्रतीत होते हैं। जम्मू में हिन्दू भावनाओं का संचार अधिक है, इसलिए आज़ाद की पार्टी के यहां भाजपा का हितसाधन करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आज़ाद घाटी में मुस्लिम मतदाताओं को तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो इससे भाजपा को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मदद मिल सकती है। आज़ाद जहां "धर्म-निरपेक्ष विचार धारा" का समर्थन करने पर कायम हैं, वहीं यह बात भी गौर करने लायक हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति सोमवार को फिर उत्साहपूर्ण अंदाज में बोला और "मानवीय संवेदनाओं" को लेकर उनकी प्रशंसा की।

पौंडरिक पार्क से पार्किंग प्रोजैक्ट वापस लिया सरकार ने

- **राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि, पौंडरिक पार्क से पार्किंग प्रोजैक्ट वापस ले लिया गया है।**
- **हाई कोर्ट में पार्किंग प्रोजैक्ट के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिन्हें अब निस्तारित कर दिया गया है।**

जयपुर, 29 अगस्त (का.सं.)। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि शहर के पौंडरिक पार्क में बनाए जा रहे पार्किंग प्रोजेक्ट को वापस ले लिया गया है। अब पार्क में पार्किंग के नाम पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा।

सरकार ने यह भी बताया कि, पार्किंग के लिए अन्य उचित स्थान की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी ने पौंडरिक पार्क विकास समिति व पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक सहित अन्य की जनहित याचिकाओं को निस्तारित किया।

जनहित याचिका में कहा गया था कि, पौंडरिक पार्क शहर की विरासत है और आमजन की भावनाएं इससे जुडी हुई हैं। ब्रहमपुरी रिहायशी क्षेत्र है और वहां पर किसी पार्किंग जगह की जरूरत ही नहीं है। लोगों का पार्क की जमीन पर अधिकार है। यदि नगर निगम को पार्किंग बनानी भी है तो पास के नाले के ऊपर बनाई जा सकती है। पूर्व महापौर ने इस पार्क को किड्स जोन बनाने के लिए कहा था, लेकिन अब मौजूदा राज्य सरकार ने वह प्लान ही बदल दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट कई मामलों में कह चुके हैं कि पार्क व ओपन स्पेस के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि सरकार ने पार्क या ओपन स्पेस के मौजूदा स्वरूप में बदलाव भी कर दिया है तो उसे वापस पुरानी स्थिति में ही लाना होगा। ऐसे में राज्य सरकार और नगर निगम को पौंडरिक पार्क में पार्किंग निर्माण की मंजूरी नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि, राज्य सरकार ने मार्च 2021 में हाइकोर्ट को बताया था की, पार्किंग प्रोजेक्ट का निर्माण रोक दिया गया है और आगामी सुनवाई तक निर्माण नहीं किया जाएगा।

'ऑपरेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काम आने वाले एक गैर कानूनी सॉफ्टवेयर का पता चला हैं। ये दलाल सीट और बर्थ की माँग और पूर्ति के अन्तर का नाजायज़ फायदा उठाया करते थे। यह रैकेट आरक्षित सीटों को घेरने तथा जरूरतमंदों को अतिरिक्त पैसा (प्रीमियम) लेकर बेचने का काम करता था। ये लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, ऑनलाइन हुये कन्फर्म रेलवे आरक्षणों का पता लगाते थे तथा आम ग्राहकों को टिकटों की उपलब्धता पर नज़र रखते थे।

रेल मन्त्रालय की एक प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया हैकि 43,44,750 रू कीमत की 688 रेलवे टिकट जब्त की गईं है। ये अपराधी टिकटें खरीद कर, 28.14 करोड़ रू. में बेच चुके थे तथा इस पर उन्होंने बहुत बड़े कमीशन की कमाई की थी। इससे बहुत बड़ी मात्रा में कालाधन सृजित हुआ था, जो अन्य अनैतिक कार्यो में काम आ सकता था

विज्ञप्ति में कहा गया है कि वॉट्सऐप तथा इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिये गैर कानूनी सॉफ्वेयर तैयार करने तथा बेचने के काम में लिप्त ये लोग आई.आर.सी.टी.सी. के नकली यूजर आई.डी. तथा नकली वर्चुअल नम्बर उपलब्ध कराया करते थे। उनके पास नकली आई.पी. पते सृजित करने वाले सॉफ्टवेयर थे ताकि वे उन प्रतिबन्धों को बाइपास कर सकें तथा प्रत्येक आई.पी. नम्बर पर सीमित संख्या में टिकट प्राप्त कर सकें। ये लोग डिसपोजेबल मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल भी बेचा करते थे जो आर.सी.टी. सी. को नकली यूजर आई.डी. सृजित करने हेतु, ओ.टी.सी. सत्यापन के काम आते हैं।

राफेल डील...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को कहा कि "कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई केस नहीं बनता है।" ज्ञातव्य है शर्मा हर मुद्दे पर याचिका दायर करने के आदी है।

अपनी याचिका स्वीकार करने के लिए कोर्ट को प्रभावित करने के लिए शर्मा ने कहा, "एक दिन आएगा जब हरेक व्यक्ति बेबस महसूस करेगा और कोई भी भ्रष्टाचार पर सवाल करने के लिए कोर्ट नहीं आएगा।

सी.जे.आई. ने शर्मा से कहा कोर्ट याचिका खारिज करने का आदेश दे चुका है। बाद में शर्मा याचिका वापस लेने के लिए मान गए जिसके लिए कोर्ट ने उन्हे अनुमति भी दे दी।

शर्मा ने कहा कि वे इस मामले में सी.बी.आई. के पास जाएंगे। कोर्ट ने कहा "आपको कोई भी नहीं रोक रहा है।"

मीडिया पार्ट, फ्रैंस ऑनलाइन जर्नल, की रिपोर्ट, जो माह के आरंभ में छपी थी।

इसमें दावा किया गया था कि उनके पास ऐसे दस्तावेज है जो बताते हैं कि राफेल निर्माता कम्पनी दसॉल्ट और उसके पार्टनर ने डील के संबंध में एक मिलियन यूरो का सीक्रेट कमीशन दिया था।

'' भेड़िया आया, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्तमान बाढ़ से गहरी आर्थिक क्षति होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन की फण्डिंग वाले बैल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (बी.आर.आई.) के अन्तर्गत नए बने नए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन यदि व्यापक विध्वंस पर गौर किया जाए तो इनका बचना भी मुश्किल है। निर्मित हो चुके गारगांतुआन बी.आर.आई. प्रोजैक्ट्स की पुनर्भुगतान जवाबदेहियों को लेकर पाकिस्तान पहले से ही जबरदस्त दबाव में हैं। इनमें कई प्रोजैक्ट्स सफेद हाथी हैं जो अपने ऋणों की अदायगी करने लायक प्रॉफिट भी नहीं कमा सके। अब जबकि ये इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बाढ़ से तबाह हो चुकी है तो देश पर अलाभकारी एवं अनुपयोगी प्रोजैक्ट्स का भार और आ जाएगा। ये पाकिस्तान के बजट और सार्वजनिक वित्त को भी प्रभावित कर सकता है। फिर भी, शाहबाज़ शरीफ सरकार पर पानी में फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री लाने का दबाव है। बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों में भोजन को लेकर आपाधापी मची है। बच्चे भी भोजन और पीने के पानी से महरूम हैं। पानी के तेज बहाव से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसलिए जब पानी उतार पर आना शुरु होगा तब उन उच्च स्थलों पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी जहां लोगों ने शरण ले रखी है। बिल्कुल पड़ोस में स्थित भारत इस संकटग्रस्त देश को अहम राहत पहुंचा सकता है, लेकिन राहत देने के लिए भारतीयों का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचना होगा जिसे पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय पसंद नहीं करेगा। भारत सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वह राहत सामग्री को पाकिस्तानी अधिकारियों के सुपुर्द कर दे और उम्मीद करे कि यह पीड़ित जनता के पास पहुंच जाए।

मणप्पुरम गोल्ड लोन कम्पनी में डकैती 12 करोड़ रू. का सोना व 11 लाख रू. नकद लूटा

शहर के सुंदरवास क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई वारदात

- **सीसीटीवी कैमरे में पिस्तौल की नोंक पर स्टाफ को डराते दिखे लुटेरे।**
- **दो बाइक पर आए थे पांच लुटेरे।**

उदयपुर 29 अगस्त, (निसं)। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित सुंदरवास क्षेत्र में सोमवार सुबह बाइक पर आए पांच लुटेरे एक बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। क्षेत्र में मण्णप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में घुस इन लूटेरों ने पहले पिस्टल की नोंक पर कर्मचारियों को बंधक बनाया और उसके बाद कंपनी में रखा चौबीस किलो सोना जिसकी कीमत 12 करोड़ रूपए आंकी गई है वहीं कंपनी में रखे 11 लाख रूपए नकद लूट ले गए। वारदात के बाद पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए संभागभर में नाकेबंदी करवाई लेकिन लुटेरे अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सवेरे प्रतापनगर थानाक्षत्र के सुन्दरवास मुख्य मार्ग पर स्थित मण्णप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में घुसते ही नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में मौजूद एक महिला सहित छ: कर्मचारियों को पिस्टल दिखा बंधक बना मारपीट शुरू कर दी। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लुटेरों ने वहां बने लॉकर से करीब चौबीस किलो सोना व ग्यारह लाख रूपये की नकदी लूट ले गए। पांच बदमाश दो बाइक पर सवार होकर चेहरे को नकाब से ढ के हुए वारदात करने पहुंचे थे। कंपनी खुलते ही अंदर घुसे दो इन लुटेरों ने कर्मचारियों को पिस्टल दिखा एक जगह इकठ्ठा कर नीचे बिठा दिया तथा उनके हाथ बांध दिए। इस दौरान बदमाशों के शेष साथियों ने पिस्टल की नोक पर लॉकर से नकदी व सोना लेकर फरार हो गए।

सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चन्द्रशील ठाकुर ने मय जाप्ता मौके पर पहुंच कर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इस पर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए रेंज में नाकाबंदी करवाई है। पुलिस की विभिन्न टीमे बदमाशों की तलाश में जुटी है।

गुलाम नबी ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाने का क्रम...

- **राहुल समर्थक यह भी आरोप लगा रहे हैं कि, जब भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बार-बार ''पप्पू'' कह कर अपमानित करते हुए कटाक्ष किया, तब कोई भी वरिष्ठ नेता, जिसमें गुलाम नबी भी शामिल हैं, राहुल के पक्ष में नहीं बोला। क्या यह वरिष्ठ, पुराने नेताओं की जिम्मेवारी नहीं थी।**
- **जब राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस में चुनाव करवाने का बीड़ा उठाया, इन वरिष्ठ, बुजुर्ग नेताओं ने राहुल को ''नासमझ'' अनुभवहीन कह कर खिल्ली उड़ाई और अब ये लोग पार्टी में चुनाव कराने के लिये अभियान सा चला रहे हैं।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा अपनी नई छवि बनाने के लिये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही है, आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा देकर राहुल की कमियाँ गिनाना शुरु कर दिया है।

आज़ाद के अनुसार, राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा था कि जिन लोगों ने प्रचार के दौरान उनके इस नारे को काम में लिया हो, वे हाथ उठायें। उस समय मीटिंग में मनमोहन सिंह, ए.के. एन्टनी, पी. चिदम्बरम तथा आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

आज़ाद ने कहा, "उन्होंने (राहुल) उन सभी लोगों से हाथ उठवाये, जिन्होंने कहा था, "चौकीदार चोर है।" वहाँ कई वरिष्ठ नेता थे, जो मुख्यमंत्री तथा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ मंत्री रह चुके थे- आप ऐसे नेताओं से ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी भाषा बोलें। हम किसी का दाँये, बाँये तथा किसी भी दिशा से विरोध कर सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते।"

आज़ाद ने कहा कि उन जैसे राजनेता ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वे अपने विरोधियों पर इस प्रकार व्यक्तिगत हमले करें। लेकिन आज़ाद पूर्व पार्टी नेता संजय गांधी के साथ गुज़ारे अपने उन दिनों को कितनी आसानी से भूल गये, जब संजय गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा अपने राजनैतिक विरोधियों पर हमले बोलते हुये, निर्लज्जता की सीमा पार कर जाते थे।

आज़ाद ने कहा, "हमने इंदिरा गांधी से राजनैतिक शिक्षा एवं संस्कार पाये हैं। जब मैं वरिष्ठ मंत्री था, तो उन्होंने एम.एल. फोतेदार और मुझे बुलाया था और कहा था कि आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते रहा करें। नेता और नेता के बीच फर्क देखिये। उन्होंने कहा था कि अटल जी राजनेता हैं, वे भी निश्चित रूप से चाहेंगे कि काम हो। वे मुझसे बात करने में संकोच करेंगे। इसलिये, आप लोग उनसे पूछते रहा करो। इस प्रकार, हमको ऐसी शिक्षा मिली थी कि हम अपने बड़ों का, वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें तथा विपक्षी नेताओं को भी उतना ही सम्मान दें। हमें यह नहीं सिखाया गया था कि हम जनता के बीच जाकर कहें कि प्रधानमंत्री चोर है। लेकिन क्या यह इस्तीफा देने का कारण है।

उन्होंने कहा, "हम मोदी पर हर तरफ से हमला कर सकते हैं, लेकिन हम उन पर इस प्रकार से व्यक्तिगत हमले नहीं कर सकते। क्या वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रह चुके लोगों को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिये?"

आज़ाद के इस्तीफे में राहुल गांधी की एक अत्यन्त तीखी टिप्पणी, उनके द्वारा 2013 में सबके सामने एक अध्यादेश को फाड़कर फैंक देने वाली घटना से संबंधित थी। आज़ाद ने इस कार्य को उनका बचकाना व्यवहार तथा उनकी अपरिपक्वता का जबरदस्त नमूना बताया था।

आज़ाद ने कहा, "इस कार्य से प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) तथा पूरे मंत्रिमण्डल के अधिकार एवं गौरव का क्षरण हुआ था। मैं नहीं जानता कि राहुल जी को आज तक भी मालूम है या नहीं कि अध्यादेश कैसे जारी किये जाते हैं। जो चीज सरकार के प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुख के नेतृत्व में पारित हुई है- आप उसे सबके सामने फाड़कर फैंक रहे हैं।"

आज़ाद ने अपने इस्तीफे में जो यह आरोप लगाया था कि "महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा यहाँ तक कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स तथा पी.ए. (पर्सनल असिस्टैन्ट्स) द्वारा लिये जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है। उन्हें पूछा कि ऐसा नेता किस प्रकार का अध्यक्ष होगा..... कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति जानता है कि वे लोग कौन हैं, जिनके जरिये लोग राहुल गांधी तक पहुँच पाते हैं।" आर.एस.एस. द्वारा लगाये जाने वाले "मदर-सन सिन्ड्रोम" के आरोप का अनुसरण करते हुये, आज़ाद ने कहा कि सोनिया गांधी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वे (सोनिया) उन पर पूरी तरह निर्भर होकर रह गई हैं।

"सभी माँ ऐसी ही होती है। सभी माँ-मेरी माँ, आपकी माँ- उनके बच्चे उनकी कमजोरी होते हैं।"

आज़ाद ने मीडिया के साथ हुई इस बातचीत में चयनित घटनाओं या बातों का ही जिक्र किया है। लेकिन राहुल को अपने हमले का निशाना बनाते हुये, वे इस बात को भूल गये कि उन जैसे वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी को "पप्पू" के रूप में चित्रित करने के आर.एस.एस.-भाजपा के संयुक्त अभियान की न तो कभी निन्दा की और न कभी आलोचना की। वे उस समय भी मौन रहे थे, जब नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राहुल के लिये अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। क्या यह वरिष्ठ नेताओं का दायित्व नहीं था कि वे उस समय अपने पार्टी-साथियों के बचाव में आगे आते, जब उनके वैचारिक प्रतिद्वंदी उन पर अनुचित एवं अशोभनीय प्रहार कर रहे थे?

राहुल का समर्थन उस समय न तो आज़ाद ने या पार्टी छोड़कर चले जाने वाले अन्य नेताओं ने किया और न उनमें से बहुत से नेताओं ने किया, जो इस समय पार्टी में हैं, जब राहुल ने चुनाव करके भारतीय युवा कांग्रेस को लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की थी। इसके बजाय, इन लोगों ने राहुल की हँसी उड़ाते हुये, चुनाव कराये जाने का एक बचकानी कोशिश बताया था, अब वे ही सब पार्टी में चुनाव कराने के लिये दबाव बना रहे हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908